



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, सोमवार, 18 जनवरी, 1993/पौष 28, 1914
No. 12] NEW DELHI, MONDAY, 18 JANUARY 1993/PAUSA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1993

विषय: अर्जेंटीना गणराज्य, ब्राज़ील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और
संयुक्त राज्य अमेरिका मूल के पोखी विनाइल क्लोराइड रेजिन
के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच—प्राथमिक निष्कर्ष

सं. 14/9/92-टी पी डी.—भारत सरकार ने, 1982 में
यथा संशोधित संसाधन शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और
उससे संबंधित नियमावली, 1985 का अद्यतन करे हुए और प्रशासनिक
मंत्रालय, नामतः उर्वरक एवं उद्योग मंत्रालय, आयात तथा पैट्रोलियम
विभाग के परामर्श से, जबकि

(क) कार्य प्रणाली

1982 में यथा संशोधित संसाधन शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के
तहत नामोद्धृत प्राधिकारी की गई, 1992 में पी. वी. म. रेजिन मैनु-
फैक्चरर्स एसोसिएशन, बम्बई द्वारा उन उत्पादकों की ओर से दर्ज की गई
एक लिखित शिकायत मिली जिसका पी. वी. म. रेजिन का सामूहिक
उत्पादन लगभग 70% रहा था, उसमें यह बताया गया कि वह मन्दोद्योग

त्पाद का भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस शिकायत में
जैन्टीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका
के इस उत्पाद के जमा होने और उसके फलस्वरूप बास्तविक क्षति
होने का प्रमाण दिया गया। इसमें आगे कार्यवाही आरंभ करने के अनिवार्य
हेतु उचित समझा गया।

(2) नामोद्धृत प्राधिकारी ने तदनुसार, भारत के राजपत्र में दिनांक
10-6-1992 का एक सार्वजनिक सूचना के द्वारा एच.एस. संसाधन
शर्त सं. 39041000, 39042102, 39042109 के तहत आने वाले
पी. वी. म. रेजिन क्लोराइड फॉर क्लोविंग पाउडर (पेस्ट अथवा बेटर्स ग्रेड का
छोड़कर) जिसमें पी. वी. म. रेजिन के सभी ग्रेडों को कवर करते हुए किन्तु
मिश्रण ग्रेड का शामिल न करते हुए और जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको,
कोरिया गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका मूल का था उसके आयात में
संबंधित एंटी-डॉपिंग का कार्यवाही आरंभ करने की घोषणा
की और जांच आरंभ कर दी।

(3) नामोद्धृत प्राधिकारी ने संबंधित निर्यातकों तथा आयातकों,
निर्यात देशों के प्रतिनिधियों और शिकायतों की सरकारों तौर पर मनाह
दी और प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पार्टियों को अपने-प्रपने विचार लिखित
रूप में प्रस्तुत करने और मुनवाई हेतु अनुरोध करने का अवसर दिया।

याचिकादाता ने अपना याचिका में भारत को निर्यात करने वाले जिन निर्यातकों तथा पी.वी.सी रेजिन के उत्पादकों का उल्लेख किया और जिन्हें नामोद्दिष्ट प्राधिकारी ने संगत जानकारी देने हेतु एक प्रस्तावना भेजी, उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

1. इलैक्ट्रोकार्ब, ब्रजेंद्र, ना
2. इन्डुवा, ब्रजेंद्र, ना
3. फॉस्टोप्लास्ट ग्राफ अमेरिका इन्क.; होस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका
4. कम्पनियन फेडोकिबिका, ब्राजील
5. बिनमार इन्क.; होस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका
6. यू.बी. इन्टर्नेशनल, सिगापुर
7. पूर्ण प्राइमैक्स सो. डि. सी. बी.; मैक्सिको
8. हानयांग केमिकल कारपो.; कोरिया
9. लक्को गोल्डस्टार इन्टरनेशनल, दक्षिण कोरिया
10. फारमूला प्लास्टिक्स कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका
11. बोर्डन केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
12. वाइन्टेक इन्क.; होस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका
13. बिस्टा केमिकल कंपनी, होस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका

4. मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज (सिगापुर) प्रा. लिमिटेड, सिगापुर ने इस बात का पृष्ठ की कि वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैसर्स बोर्डन केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स, सं. रा. अमेरिका ने कहा कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान सस्पेंशन ग्रेड के पी.वी.सी रेजिन का निर्यात नहीं किया था। किन्तु, उन्होंने यह बताया कि उनके द्वारा विनिमित उत्पादों का संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात हुआ था। इनका निर्यात साधारणतया उन निर्यात कंपनियों द्वारा किया गया जिनको उन्होंने माल बेचा था और संयुक्त राज्य अमेरिका में माल का नाम हस्तांतरित किया था। उन्हें न तो यह मालूम था कि इन उत्पादों को किस काम पर पुनः बेचा गया और न ही यह कि उनकी किसे बेचा गया था। ब्रजेंद्र, ना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी ने भी जिन्हें भारतीय पी.वी.सी रेजिन मैफ़ैक्चरर्स एसोसिएशन की शिकायत के बारे में सूचित किया गया था और जिससे परिचालित प्रस्तावलों के अनुसार संबंधित जानकारी उल्लेख कराने का अनुरोध किया गया था, निरधारित समय सीमा के अंतर प्रस्तावलों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिन निर्यातकों ने परिचालित प्रस्तावलों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था वे भी बढ़ाई गई समय-सीमा के अनुसार जानकारी उल्लेख कराने में असफल रहे। केवल कोरिया गणराज्य के नई दिल्ली स्थित दूतावास के प्रतिनिधि श्री एस. सी. चण्ण कर्णिकियक सहायक सी बिनिक 8 अक्टूबर, 1992 को हुई सुनवाई में, उपस्थित हुए और उन्होंने कोरिया गणराज्य के निर्यातकों की ओर से प्रतिपादित किया

भारत के पी.वी.सी उत्पादों के अनेक उत्पादकों और प्रयोजन संघों ने भी अपने-अपने निवेदन प्रस्तुत किए। ये संघों में इस प्रकार हैं:—

- (क) घरेलू उत्पादन स्तर हो गया है जिससे मांग तथा पूर्ति के अंतर को घटाने के लिए, आयात की आवश्यकता हुई है।
- (ख) घरेलू कोमल ऐतिहासिक रूप से अनेकता कम और आयातित कोमल की तुलना में प्रतियोगी रही है।
- (ग) किमी देश का निहाज किए बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से विनिर्माताओं द्वारा वसूल की गई कामों विभिन्न क्वालिटीयों के लिए हाल ही में सीमा के अंतर अर्थात् 530 से 580 अमेरिकी डॉलर में टन के बीच रही है।
- (घ) पी.वी.सी रेजिन की अन्तर्राष्ट्रीय कामलों में 1991 के पूरे वर्ष में लगभग गिरावट होती रही।
- (ङ) जनवरी-मार्च, 1992 के दौरान अनेकता अधिक आयात इस कारण से हुआ कि उद्योगकारों में यह डर रहा कि 1992-95 की अवधि के लिए घोषित होनेवाला नीति में आयात पर कहीं प्रतिबंध न लग जाए।

(च) आयातित पी.वी.सी रेजिन की क्वालिटी गटिया है।

(6) नामोद्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजन से आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी मांगी और उसकी पड़ताल की।

(7) दक्षिण संबंधी जांच में दिनांक 1 अप्रैल, 1991 में 31 मई, 1992 तक की अवधि कवर की गई।

(ख) विचारणीय उत्पाद, जैसे हैं उत्पाद और भारतीय उद्योग

1. विचारणीय उत्पाद

(8) इस एण्ट्री डीपिंग कार्यवाही आरंभ करने संबंधी दिनांक 10-6-1992 की सांवेजनिक सूचना में संबंधित उत्पाद है। पी.वी.सी रेजिन क्लोराइड रेजिन आइड की क्लोविंग पाउडर (पेस्ट अथवा पैटिंग ग्रेड की छोड़कर) जो एच.एस. सी.मा.शुल्क श.सं. 39041000, 39042102 और 39042109 के अन्तर्गत आता है और जिसमें सभी ग्रेड कवर होते हैं तथा शामिल होते हैं किन्तु पी.वी.सी रेजिन का मिश्रण ग्रेड शामिल नहीं होता है। इसे आमतौर पर पी.वी.सी रेजिन क्लोराइड रेजिन (सस्पेंशन) कहा जाता है (जिसे इसके बाद पी.वी.सी रेजिन कहा गया है)।

यह उत्पाद एक ऐसी आधारीक सामग्री है जिसका प्रयोग फुटबलर विनिर्माण के लिए और तारों तथा केबलों की कोटिंग तथा इंसुलेशन प्रयोजनों के अतिरिक्त पाइपों (अधिकांश 40 प्रतिशत) प्लास्टिक के अन्य घरेलू सामान के विनिर्माण और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोग में किया जाता है।

(9) हालांकि बेचे गए पी.वी.सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) के संभावित प्रयोग और क्वालिटी में अंतर तो हो सकता है लेकिन इससे एच.एस. सी.मा.शुल्क श.सं. 39041000, 39042102 तथा 39042109 के अर्थात् आने वाले पी.वी.सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) की विभिन्न किस्मों की मूल वार्षिक विनिर्माणों उद्योगकारों के अवधीन अथवा विपणन में कोई अधिक अंतर नहीं आता है इसलिए इसे इस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए एक उत्पाद समझा जाए।

2. समरूप उत्पाद

10. ब्रजेंद्र, ना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को जो पी.वी.सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड)

5. परिवर्तित भारतीय उत्पादकों ने अपने विचार लिखित में दिए। ये संघों में निम्नानुसार हैं:—

- (1) संबंधित देशों के मूल के पी.वी.सी रेजिन का निर्यात कायम उसकी सामान्य कामत से कहीं कम रही।
- (2) संबंधित देशों से हुए आयात से भारतीय उत्पादकों को वास्तविक क्षति हुई।
- (3) भारतीय उत्पादकों को घरेलू कोमल उचित मूल्य से भी कम करने के लिए मजबूर किया गया है और इस तरह उन्हें बहुत हानि/लाभ का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- (4) भारतीय उत्पादक अपना बाजार हिस्सा खो रहे हैं और आमतौर पर जमा स्टॉक से कहीं अधिक मात्रा जमा हो रहा है।

निर्यात होता है वह भारत में उत्पादित तथा विपणन किए जाने वाले चीनी, रेजिन (सर्वेशन ग्रेड) का तुलना में हर प्रकार से कुल मिलाकर एक जैसा ही है।

3. भारतीय उद्योग

(11) परिवारों को यह अवधारणा कि व इस तरह के उत्पाद के कुल अथवा उत्पादन के 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और, इस प्रकार, यह सामाजिक टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं पर शुल्क अथवा प्रतिरिक्त शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन तथा संग्रह और क्षति के निवारण) नियमावली, 1985 के पैरा 2 (सी) के अनुसार इसके कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है जिसकी प्रशासनिक विभाग अर्थात् रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग ने पड़ताल की थी और सही पाया था।

ग. सामान्य मूल्य

निर्यातक देशों में कीमत-निर्धारण पर आधारित सामान्य मूल्य।

12. चूंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उन्हें भेजा गई प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में वास्तविक जानकारी नहीं दी थी इसलिए, उपरोक्त नियम 14 के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना आवश्यक समझा गया।

घ. निर्यात मूल्य

(13) प्राधिकारों ने भारतीय सामाजिक प्राधिकारियों से इस तरह की जानकारी प्राप्त की जिसमें जांच की अवधि के दौरान हुए प्रमुख आयात कवर हों। प्राप्त जानकारी को इस अवधि के दौरान निर्यातक देशों अर्थात् अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सौदों का चोटक समझा गया।

(14) चूंकि किसी भी निर्यातक ने संगत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकारों के अनुरोध का प्रत्युत्तर नहीं दिया अतः निर्यात कीमतों संबंधित उत्पादों के लिए वास्तव में दी गई कीमतों के आधार पर निर्धारित की गई थी जिसकी प्रतीति पाई गई किन्तु कोरिया गणराज्य के प्रतिनिधि ने यह बात स्वीकार की कि उनकी निर्यात कीमतों पर डम्प कीमतों से कम रही।

ङ. तुलना

(15) सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच एक स्पष्ट तुलना के प्रयोजन हेतु और सत्यापन शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (2) तथा उपरोक्त नियम 14 के अनुसार प्राधिकारों ने अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों से जिनसे उनकी और ने संगत जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, कोई उत्तर नहीं मिल पाने के बजाय से सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी की ध्यान में रखा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंतिम तुलना एक ही स्तर पर की गई।

च. डंपिंग मार्जिन

(16) चूंकि निर्यात कीमतों में काफी अंतर रहा, अतः निर्यात की घरेलू बाजार में बेची गई किस्म के सामान्य मूल्य की तुलना अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध जानकारी के आधार पर तुलना किस्म के एक ही चीनी की निर्यात कीमत से की गई। डंपिंग का मार्जिन अलग-अलग देशों में अलग-अलग रहा किन्तु भारत में इन देशों के सभी मूल आयातों का औसत मार्जिन काफी रहा।

(17) प्राधिकारों ने सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित देशों से चीनी रेजिन (सर्वेशन ग्रेड) के आयात के संबंध

में निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और डंपिंग के मार्जिन का प्रारंभिक निवारण इस प्रकार किया—

देश	निर्यात कीमत एफ.ओ.बी.	सामान्य मूल्य	डंपिंग का मार्जिन
	(अमेरिकी डालर प्रति टन)	(अमेरिकी डालर प्रति टन)	(सी.आई.एफ. मूल्य का प्रतिशत)
अर्जेंटीना			
ब्राजील			
कोरिया गणराज्य			
मैक्सिको			
सं.रा. अमेरिका			

छ. क्षति

(18) प्राधिकारों का यह विचार है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से किये जा रहे आयातों के प्रभावों का कुल मिलाकर विश्लेषण किया जा रहा था। संबंधित प्रत्येक देश के निर्यातित उत्पाद एक जैसे उत्पाद थे जो कि एक ही बाजार में बेचे गये थे अथवा किसी के जिन पेज किये गये थे, उनके वितरण के माध्यम सामान्य अथवा एक जैसे थे। ये उत्पाद बाजार में एक साथ विद्यमान थे और इस प्रकार से ये नगण्य नहीं थे। फलस्वरूप इन आयातों का घरेलू उद्योग पर एक समान और एक साथ प्रभाव पड़ा जिनका मूल्यांकन संवित रूप में किया जाता जरूरी है।

(19) नियम 18 संपरा के अंतर्गत वास्तविक क्षति अथवा उसकी आंशिकता के प्रश्न पर निश्चय करने के लिये नामित प्राधिकरण को "डम्प किये गये आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में उसी प्रकार उत्पादों के लिये उनकी कीमतों पर पड़ने वाले उससे प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के प्रभाव" पर विचार करना पड़ता है। जहां तक डम्प किये गये आयातों की मात्रा का संबंध है नामित प्राधिकारों ने इस बात को ध्यान में रखा कि क्या डम्प किये गये आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डम्प किये गये आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए इस बात की जांच करना जरूरी समझा जाता है कि क्या भारत में उसी प्रकार के उत्पाद की कीमतों की तुलना में डम्प किये गये आयातों से कीमत में बहुत अधिक कमी आई है अथवा ऐसे आयातों का अथवा उल्लेखनीय सीमा तक कीमतें कम करने या क्षयितों में ऐसी वृद्धि की रोकने पर प्रभाव पड़ा है जो कीमत वृद्धि डम्प किए गए माल के अभाव में होती थी।

(20) भारत में उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिये नामित प्राधिकरण ऐसे संकेतों पर विचार करता है जिनका क्षमता के उपयोग, माल सूची, लाभों और कीमत प्रवृत्तियों के रूप में उद्योग की स्थिति से संबंध होता है।

भारत में खपत

(21) वर्ष 1988-89 से 1990-91 की अवधि के दौरान भारतीय बाजार का आकार अपेक्षाकृत स्थिर रहा। कुल बाजार का अनुमान 1988-89 में 2,48,000 मीट्रिक टन, 1989-90 में 2,82,000 मीट्रिक टन तथा 1990-91 में 2,40,000 मीट्रिक टन रहा। चीनी रेजिन (सर्वेशन ग्रेड) की उपलब्धता 1991-92 के दौरान लगभग 3,39,000 मीट्रिक टन रही थी, जो 1988-89 की तुलना में लगभग 21% अधिक है।

डम्प किं गये आयातों की मात्रा तथा बाजार शेयर

(22) जांच अधीन देशों से आयात 88-89 में 62,307 एम टी से बढ़कर 90-91 में 87,942 एम टी हो गये और 91-92 में और बढ़कर 140,909 एम टी हो गये। यह उल्लेखनीय है आयात में कमी के गम्भीर उपाय लागू किये जाने के बावजूद 1991-92 में आयातों में तीव्र वृद्धि हुई। 19-3-91 को ओ जी एल आयातों पर 133% का तथा विशेष लाइसेंसों पर 125% का कंश माहित लागू किया गया था। इसे 8-10-91 को कम करके 150%, 9-12-91 को 50%, 1-1-92 को 25% करने से पहले 22-4-1991 को बढ़ाकर 200% कर दिया गया था और 12-2-1992 को इसे अस्तित्व हटा दिया गया। जैसे ही आयात कम करने के उपाय में छूट दे दी गई डम्प किये गये आयातों में उभार आ गया। जांच अधीन देशों से होने वाले आयात वर्ष 1991-92 के पहले ग्यारह महीनों के दौरान 10,829 एम टी प्रति माह से जी मार्च 1992 में बढ़कर 21,794 एम टी हो गये। आयातों में यह वृद्धि श्रीलंका के संबंध में मार्च 92 माह में 6185 एम टी की हुई जबकि पहले ग्यारह महीनों में 3968 एम टी प्रति माह का औसत स्तर था। यह वृद्धि मैक्सिको के संबंध में 925 एम टी से बढ़कर 8626 एम टी, कोरिया गणराज्य के संबंध में 2596 एम टी से बढ़कर 3582 एम टी और संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में 3134 एम टी से बढ़कर 3322 एम टी हो गई।

(23) जांच में शामिल देशों से आयातों का बाजार शेयर 1988-89 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 31 प्रतिशत तथा इसके बाद 1991-92 में 43 प्रतिशत हो गया।

डम्प किए गए आयातों की कीमतें

(24) नामित अधिकारी ने यह जांच की कि क्या अर्जेंटीना, ब्राजील कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातकों ने जांच की जा रही अवधि के दौरान कीमतों में कमी की थी। यह देखा गया कि अवधि 1991 की पहली तिमाही में यह औसत कीमत लगभग 800 डालर प्रति मीट्रिक टन सी आई एफ बी तथापि 1991 की दूसरी तिमाही में सी आई एस के आधार पर यह कम होकर लगभग 700 डालर प्रति मीट्रिक टन और 1991 की तीसरी और चौथी तिमाही में सी आई एफ आधार पर यह कम होकर लगभग 560 डालर प्रति मीट्रिक टन रह गई। 1992 की पहली तिमाही में औसत सी आई एफ कीमत लगभग 530 डालर प्रति मीट्रिक टन थी।

(25) ऊपर की गई तुलना से यह पता चलता है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमरीका के निर्यातकों की ओर से उल्लेखनीय रूप से कीमत में कमी की गई है।

उद्योग पर अत्यंत नगण्य आर्थिक कारका प्रभाव

संस्थापित क्षमता एवं क्षमता उपयोग

(26) भारतीय पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) उद्योग की संस्थापित क्षमता वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1991-92 के दौरान 1991-92 के दौरान क्रमशः 141700, 148440 तथा 186973 एम. टी. थी। जबकि 1,00,000 एम. टी. की क्षमता वाले आर. पी. एल. ने दिसम्बर, 1991 में उत्पादन शुरू कर दिया था और कैप्लास्ट ने अपनी क्षमता 13200 एम टी से बढ़ाकर 28,800 एम. टी. वार्षिक कर दी। यह भी दिसम्बर, 1991 से प्रभावी है। पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) की कुल संस्थापित क्षमता वार्षिक आधार पर 31 मार्च, 1992 को 2,64,040 एम. टी. थी।

(27) भारतीय उद्योग की पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) का उत्पादन 1988-89 में 1,22,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1991-92 में 1,63,000 मीट्रिक टन हो गया।

(28) पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) का क्षमता उपयोग 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान लगभग 86% 1990-91 से 89% और 1991-92 में 87% था।

माल सूची

(29) उद्योग की पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) की अंतिम स्टॉक स्थिति निम्नलिखित से देखा जा सकती है :-

31-3-89	5851 एम. टी.
31-3-90	5247 एम. टी.
31-3-91	2967 एम. टी.
31-3-92	16696 एम. टी.

(आई पी सी एल को छोड़कर)

वित्तीय वर्ष 1991-92 के अस्त में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक इकट्ठा हो गया था।

विक्री की मात्रा तथा भारतीय उद्योग का बाजार शेयर

30. भारत के उपलब्ध स्वदेशी पी वी सी रेजिन (सस्पेंशन ग्रेड) की मात्रा वर्ष 1988-89 और 1991-92 के बीच लगभग 34% तक बढ़ गई। 1988-89 में यह 1,22,000 मीट्रिक टन थी जो 1991-92 में बढ़कर 1,63,000 मीट्रिक टन हो गई। कुल उपलब्धता में भारतीय उद्योग का योगदान 1988-89 में लगभग 49%, 1989-90 में लगभग 45%, 1990-91 में लगभग 48% तथा 1991-92 में लगभग 49% रहा।

लाभप्रदता

(31) चार आवेदक कंपनियों में से केवल तीन कंपनियों अर्थात् श्रीराम, डी सी डब्ल्यू और कैमप्लास्ट ने अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें अद्यतन वर्ष 1991-92 के लाभ हानि खाते सहित अपने तुलन पत्र दर्शाए हैं। श्रीराम कंपनी आर पी एल ने वर्ष 1990-91 तक की अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। उस समय इसने पी वी सी का कोई उत्पादन नहीं किया था। ये तीनों कंपनियां 1991-92 में लाभ कमा रही थी। श्रीराम और डी सी डब्ल्यू के मामले में कर पूर्व लाभ बढ़ गए हैं। जबकि कैमप्लास्ट के मामले में 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान गिरावट आई। तथापि, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये सभी बहु उत्पाद कंपनियां हैं।

कीमत प्रवृत्तियां

(32) घरेलू उद्योग की कीमत प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि वर्ष 1989-90 के पिछले छः महीनों में हुई मामूली सी गिरावट को छोड़कर वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान नियमित वृद्धि हुई। वर्ष 1991-92 के शुरू में यह वृद्धि कायम रही लेकिन जनवरी, 1992 से लगातार गिरावट चल रही है। कैमप्लास्ट, डी सी डब्ल्यू, एस एफ सी तथा आर पी एल को फेक्टरी से निकलते समय अधि-प्रति में दिसम्बर, 1991 तथा मार्च, 1992 के बीच क्रमशः 9.7, 6.1, 9.5 तथा 11.4 प्रतिशत की गिरावट आई। चूंकि जांच अधीन आदेशों से होने वाले आयातों में जनवरी से मार्च, 1992 की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है, अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू तौर पर उत्पादित पी वी सी रेजिन की कीमत में यह गिरावट डम्प किए गए आयातों की वजह से आई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 1991 तथा मार्च, 1992 के बीच जांच अधीन पांच देशों में से चार देशों के संबंध में प्रति एम टी औसत मासिक सी आई एफ मुख्य में कमी आई। हालांकि इस वर्ष के दौरान अप्रैल, 1991 में 1 अमरीकी डालर = 19.62 रु. के स्तर से बढ़ाकर मार्च, 1992 में 1 अमरीकी डालर = 19.41 रु. तक महत्वपूर्ण विनिमय दर समायोजन किया गया था।

वास्तविक क्षति के प्रश्न पर निष्कर्ष

(33) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नियम 18 संपरा की व्याख्या के भीतर भारतीय उद्योग वास्तविक क्षति से ग्रस्त हैं अथवा उन्हें वास्तविक क्षति की आशंका है, नामित प्राधिकरण ने निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया :—

1. अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले आयातों का बाजार शेयर 1988-89 में 25 प्रतिशत था जो 1991-92 में बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया।

2 वर्ष 1991-92 की पहली तिमाही के दौरान इन स्रोतों से होने वाले आयातों में उछाला आया, क्योंकि देश में आयात में कमी संबंधी उपाय धीरे-धीरे समाप्त कर दिए गए थे।

3. सभी निर्यातकों द्वारा व्यापक रूप से कीमतों में कमी की गई थी।

4. देश में क्षमता उपयोग में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

5. सामान सूची में 31-3-92 की पिछले वर्ष उसी तारीख को विद्यमान माल सूची की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सामान सूची में वृद्धि होने का एक महयोगी कारण अनिश्चित धरेलू उत्पादन था।

6. कीमत प्रवृत्तियाँ जो निरन्तर ऊपर की ओर बढ़ रही थीं उनमें 1991-92 की अंतिम तिमाही में गिरावट आ गई। डम्प किए गए आयातों के पांच स्रोतों में से चार स्रोतों से किए जाने वाले आयातों का सी आई एफ मूल्य, रुपये के विनिमय मूल्य का पर्याप्त रूप से अधोमुखी समायोजित किए जाने के बावजूद वर्ष की अंतिम तिमाही में रुपये के रूप में गिरा है।

7. जांच प्रचीन सभी देश पी वी सी रेंजिन (स्पेंशन ग्रेड) के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं।

(34) यह निर्धारण करने के लिए कि क्या भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति की आशंका इन डम्प किए गए आयातों की वजह से हुई है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया है।

(क) भारत सरकार द्वारा किए गए आयात कम करने के उपायों के बावजूद वर्ष 1991-92 के दौरान डम्प किए गए आयातों के स्रोतों से होने वाले आयातों में वृद्धि हुई है।

(ख) डम्प किए गए आयात पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान कुल आयातों का बढ़ता हुआ अनुपात है, डम्प किए गए आयातों का यह अनुपात 1991-92 के दौरान बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया।

(ग) वर्ष 1991-92 की अंतिम तिमाही के दौरान उस समय आयातों में उछाल आया जब आयात में कमी संबंधी उपाय धीरे-धीरे कम कर दिए गए थे और ये आयात मुख्य रूप से डम्प किए गए आयातों के स्रोतों से दिए गए थे।

(घ) 1991-92 की पिछली तिमाही में कीमत में गिरावट और डम्प किए गए आयातों में उछाला साथ-साथ आया और इन आयातों से ही स्पष्ट रूप से कीमत में कमी आई। कीमत में इस कमी की वजह से ही वास्तविक क्षति की आशंका को निर्धारण करने की मुख्य रूप से जरूरत पड़ी।

(35) भारतीय पी वी सी रेंजिन उद्योग (स्पेंशन ग्रेड) का क्षमता उपयोग 1990-91 तक लगातार बढ़ता रहा परन्तु 1991-92 में इसमें गिरावट आ गई। आवेदक श्रीगम, कम प्लास्ट और डी सी डब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत प्रकाशित वित्तीय लेखाओं द्वारा लाभदायकता में गिरावट नहीं दर्शाया गया है। फिर भी वित्तीय लेखा बड़े उत्पाद कम्पनी के लिए हैं, वे इसके निष्पक्ष प्रमाण नहीं हैं कि उद्योग पी वी सी रेंजिन (स्पेंशन

ग्रेड) को बिक्री पर पर्याप्त लाभ कमता रहा है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि धरेलू उद्योग को वास्तविक नुकसान हुआ है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यदि 1991-92 की अंतिम तिमाही का कीमत प्रवृत्ति और डम्प किए गए आयातों में तब उछाल की कायम रखा जाता तो लाभदायकता में गिरावट आती और परिणामस्वरूप राजगार, वेतन, क्षमता उपयोग और निवेश से विन्यय आग में निश्चित रूप से गिरावट आती। मालगुना में पहले ही धर्मगामों प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। नामित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि विश्व मांग और आपूर्ति में समग्र असंतुलन और विश्व बाजारों में मन्दी के हालात निर्यातक देशों का डम्प की गई कीमतों पर बेचने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि डम्प किए गए आयातों के लिए धरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

भारतीय उद्योगों का हित

आम धारणा

(36) एंटी डम्पिंग शुल्कों का उद्देश्य ऐसी डम्पिंग को समाप्त करना है, जो भारतीय उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है या जिससे वास्तविक क्षति की आशंका है और भारतीय बाजार में खुला और निष्पक्ष प्रति-योगिता स्थापित करना जो मूलतः देश के आम हित में है।

(37) हालांकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि एंटी डम्पिंग शुल्क लगाने से भारतीय बाजार से सम्बंधित निर्यातकों का कीमत स्तर प्रभावित होगा और नतीजतन उनके उत्पादों की अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, तथापि ऐसी आशा नहीं है कि एंटी डम्पिंग उपाय करने से, खासकर तब जबकि एंटी डम्पिंग शुल्क की उपाही क्षतिपूर्ति की आवश्यक राशि तक सीमित है, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। इसके विपरीत डम्पिंग प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभों का निराकरण इस तरह परिकल्पित किया गया है कि यह भारतीय उद्योग को पतन में आने का रोक सके और, इस प्रकार, उत्पादकों के व्यापक हितों का उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सके।

(38) प्राधिकारी ने अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और सं.रा. अमेरिका से आयातित पी वी सी रेंजिन (स्पेंशन ग्रेड) पर एंटी डम्पिंग शुल्क के प्रभावों पर भारतीय उद्योग और उपभोक्ता सहित अन्य इच्छुक पक्षों के विशेष हितों के सम्बंध में विचार किया है और उसे संतुलित बना दिया है।

भारतीय उद्योग के हित

(39) भारतीय उद्योग को होने वाली वास्तविक क्षति की आशंका की प्रवृत्ति और खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब भारतीय उद्योग में नई क्षमता आ गई है इसे तब डम्प किए गए आयातों द्वारा उत्पन्न अहितकर हानियों में लागू किया गया, प्राधिकारी का विचार है कि हस्तक्षेप के न किए जाने पर कुछ भारतीय उत्पादकों के लुप्त हो जाने की पूरी संभावना है। इससे कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आ सकती है और इससे इच्छित आपूर्तिकर्ताओं में कटौती हो सकती है जो उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।

अन्य पक्षकारों का हित

(40) ऐसा तर्क दिया गया है कि एंटी डम्पिंग उपाय करना भारतीय जनहित के प्रतिकूल होगा क्योंकि इससे कीमतें बढ़ेंगी, प्रतिस्पर्धा कम होगी और अन्य भारतीय उद्योगों को क्षति हो सकती है।

(41) यद्यपि यह स्पष्ट है कि अनुचित प्रक्रियाओं पर आधारित कीमत लाभ नाजायज है और ये आगे चलकर उस समय उपभोक्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं जब उनके प्रभाव से प्रति स्पर्धी कमजोर पड़ जायेंगे और उनके लुप्त होने को बढ़ावा देंगे। इस मामले में यह अस्पष्ट है कि टर्निंग प्ले की वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए

मंत्रालयक उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप कीमतों में पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि पी वी सी रेजिन ही केवल एक ऐसा कच्चा माल है जिसकी उपभोक्ता के पास पहुँचाने से पहले प्रसंस्कृत करना पड़ता है।

(42) जहाँ तक प्रसंस्करण उद्योग का संबंध है इस तथ्य की देखते हुए कि अनेक भारतीय संस्थाओं और निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धी काम नहीं होगा। कम कीमतों में वृद्धि एक सीमित सीमा तक ही होने की आशा है।

निष्कर्ष

(43) निष्कर्षतः, अन्तर्गस्त विभिन्न हितों को संतुलित करने के पश्चात्, प्राधिकारी का यह विचार है कि वर्तमान मामले में उपाय करने से डम्पिंग प्रक्रियाओं के हानिकार प्रभाव समाप्त करके उचित प्रतिस्पर्धा पुनःस्थापित होगी।

(44) इसलिये प्राधिकारी का विचार है कि अन्तिम एंटी डम्पिंग शुल्क के रूप में एंटी डम्पिंग उपाय करना भारतीय जनता के आम हित में होगा।

(45) अन्तिम शुल्क के स्तर को स्थापित करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने प्राप्त डम्पिंग मार्जिनों तथा वास्तविक क्षति समाप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क राशि को भी ध्यान में रखा है, जिसे भारतीय उद्योग द्वारा बनाए रखने की संभावना है।

(46) कुंकि वास्तविक क्षति की आशंका कलेंडर वर्ष, 1992 के दौरान डम्प किए गए आयातों में उछाले से आए कीमत दबाव के कारण हुई है और व्यापक रूप से विनिमय दर समायोजन 30 फरवरी, 1992 को हुआ अतः जब प्रवधि के दौरान उत्पादों के लिए भारित औसत निर्यात कीमतों की आधार माना गया। इन कीमतों में मूल और सहायक सीमा शुल्क जोड़ दिया गया था ताकि भारत में प्रवेश करते समय उत्पाद की कीमत निर्यात की जा सके। भारत में उत्पादन लागत निर्धारित करने के उद्देश्य से उत्पादन की प्रतिनिधि भारतीय लागत का लिया गया और जब प्रवधि के लिए आंकड़ों के आधार पर हिसाब लगाया गया। उपर्युक्त लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद घरेलू कीमतों की तुलना डम्प किए गए आयातों की उत्तरसे समय की कीमत से की गई थी। उत्पाद शुल्क और प्राधिकारी शुल्क दोनों की इस हिसाब से अलग कर दिया गया था। घरेलू और आयातित कीमतों के बीच यह तुलना उस शुल्क की राशि को निकालने के लिए की गई थी वास्तविक क्षति की आशंका को समाप्त करने के लिए आवश्यक थी।

उपसंहार

(47) संक्षेपेण प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि :—

- (1) अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एच.एस. नामावली कोड सं. 39041000, 39042102 और 39042109 के अन्तर्गत आने वाले पी वी सी रेजिन को भारत में सामान्य मूल्य से कम पर बेचा।
- (2) भारतीय उद्योग वास्तविक क्षति की आशंका का सामना कर रहा है।
- (3) डम्प किए गए आयात और वास्तविक क्षति की आशंका के मध्य आकस्मिक संबंध है।

सिफारिशें

(48) भारतीय एंटी डम्पिंग विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत डम्पिंग के बराबर एंटी डम्पिंग शुल्क वसूल करना उचित रहेगा। फिर भी उपभोक्ता उद्योग के हितों की ध्यान में रखते हुए नामित प्राधिकारी इस संबंध में गंभीर अधिभूतना की तारीख से प्रत्येक देश के नाम के सामने

की गई दर से चार महीनों की अवधि के लिए अन्तिम एंटी डम्पिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है :—

देश		दर प्रति एमटी
अर्जेंटीना	1050	एक हजार पचास रुपये
ब्राजील	2490	दो हजार चार सौ नब्बे रुपये
मेक्सिको	2070	दो हजार सत्तर रुपये
कोरिया गणराज्य	1700	एक हजार सत्तर रुपये
संयुक्त राज्य अमेरिका	1970	एक हजार नौ सत्तर रुपये

(49) अन्तिम एंटी डम्पिंग शुल्क की सिफारिश स्पष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिशत के बजाय रुपये प्रति मेट्रिक टन के रूप में दी गई है। यह सुझाव सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद दिया जा रहा है। यह अन्तिम एंटी डम्पिंग शुल्क अन्य आर्थिक शुल्कों की तरह नकद वसूल किया जायगा।

(50) यह शुल्क इन देशों से नए या किसी अन्य निर्यातक पर भी लागू होगा जो वर्तमान प्रक्रियाओं के पक्ष में नहीं है।

(51) संबंधित पक्ष/निर्यातक इस अन्तिम आदेश रक्षो शुल्क की अधिवृत्ति की तारीख के एक माह के अन्दर अपने विचार बताने के लिए प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन करें।

जी. मुन्दरम, नामित प्राधिकारी और अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1993

Subject.—Anti-dumping Investigation concerning Import of Poly Vinyl Chloride Resin originating from the Republic of Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the United States of America—Preliminary findings.

No. 14/9/92-TPD.—The Government of India,

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1982 and the Rules, 1985 thereof, after consultation with the administrative Ministry, namely, the Ministry of Fertilisers and Chemicals, Department of Chemicals and Petrochemicals,

Whereas

A. PROCEDURE

In May, 1992, the Designated Authority under the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1982, received a written complaint lodged by the P.V.C. Resin Manufacturers Association, Bombay, on behalf of the producers who had a collective output of P.V.C. Resin being about 70 per cent, was stated to constitute a major portion of India's production of the product in question. The complaint contained evidence of dumping of the product concerned originating in Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. and of material injury resulting therefrom which was considered sufficient to justify the initiation of a proceeding.

(2) The Designated Authority accordingly announced by a public notice dated 10-6-1992 in the Gazette of India, the initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports into India of PVC Resin White Free Flowing Powder (other than Paste or Battery Grade) falling under H.S. Customs Heading Nos. 39041000, 39042102, 39042109 covering and including all grades but excluding emulsion grade of PVC Resin and originating in Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. and commenced investigation.

(3) The Designated Authority officially advised the exporters and importers known to be concerned, the representatives of the exporting countries and the complainant and gave them

parties directly concerned the opportunity to make their views known in writing and to request a hearing. The names of exporters to India and Producers of PVC Resin who were named by the petitioners in their petition and to whom Designated Authority addressed a questionnaire to elicit relevant information are as follows :—

1. ELECTROCLOR, Argentina
2. INDUPA, Argentina
3. KUNSTOPLAST OF AMERICA INC., Houston, USA
4. COMPANHIA PETROQUIMICA, Brazil
5. VINMAR INC., Houston, USA
6. U. B. INTERNATIONAL, Singapore
7. GRUPO PRIMEX C.A. De C.V., Mexico
8. HANYANG CHEMICAL CORPN., Korea
9. LUCKY GOLDSTAR INTERNATIONAL, South Korea
10. FORMOSA PLASTICS CORPORATION, USA
11. BORDEN CHEMICALS AND PLASTICS, USA
12. SHINTECH INC., Houston, USA
13. VISTA CHEMICAL COMPANY, Houston, USA

(4) M/s. United Breweries (Singapore) PTE Limited, Singapore, confirmed that they did not wish to make any comment. M/s. Borden Chemicals and Plastics, USA, stated that they had not exported suspension grade PVC Resin during the period of investigation. They, however, added that the products manufactured by them were exported from the United States of America. They were usually exported by the export companies to whom they sold and transferred title to the goods in the United States and they did not know at what prices these products were resold, nor to whom these were resold. None of the other producers/exporters from Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. who were informed about the complaint of Indian PVC Resin Manufacturers Association and requested to make available relevant information, as per the questionnaire circulated for the purpose, responded to the questionnaire within the specified time limit. Exporters, who made a request for extension of time limit for submitting information as per questionnaire circulated, also failed to make available the information even as per extended time limit. Only Shri S. C. Chung, Commercial Attache, a representative of the Embassy in New Delhi of the Republic of Korea, appeared at the hearing on 8th October, 1992, and deposed on behalf of the exporters in Republic of Korea.

(5) The complainant Indian producers made their views known in writing. These are briefly as follows :—

- (i) The export price of PVC Resin originating from the concerned countries were well below their normal value.
- (ii) Imports from the concerned countries have caused material injury to the Indian producers.
- (iii) The Indian producers have been compelled to reduce domestic price below the fair price and hence are suffering substantial losses/or loss of profits.
- (iv) The Indian producers are losing their market share and piling inventories far in excess of the normally held stocks.

A number of PVC product producers in India and user associations also made submissions. These are briefly as follows :—

- (a) Domestic production has remained static necessitating imports to bridge the gap between demand and supply.
- (b) Domestic prices have been lower historically and competitive vis-a-vis imported price.

(c) The price charged by the manufacturers from international market irrespective of the country have been within the limits for various qualities between Dollars 530—580 per tonne recently.

(d) The decline in international prices of PVC resin has been continuous throughout 1991.

(e) The relatively larger imports during January—March, 1992 were on account of the fear amongst the consumers that the imports might be restricted in the policy to be announced for the period 1992—95.

(f) The quality of imported PVC resin is inferior.

(6) The Designated Authority sought and verified information it deemed to be necessary for the purpose of a preliminary determination.

(7) The investigation of dumping covered the period from 1st April, 1991 to 31st May, 1992.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, LIKE PRODUCT AND INDIAN INDUSTRY.

1. Product under consideration.

(8) The product concerned by the public notice dated 10th June, 1992 of initiation of this anti-dumping proceeding is Poly Vinyl Chloride Resin White Free Flowing Powder (other than Paste or Battery Grade) falling under H.S. Customs Heading Nos. 39041000, 39042102 and 39042109 covering and including all grades but excluding emulsion grade of PVC Resin : it is commonly referred to as Poly Vinyl Chloride Resin (Suspension) (hereafter referred to as PVC Resin).

This product is a basic material used in the manufacturing of Pipes (almost 40 per cent), other plastic goods of household and industrial and commercial use besides use of this product for footwear manufacture and for coating and insulation of wires and cables purposes.

(9) Although the potential use and the quality of the PVC Resin (Suspension Grade) sold may differ, this does not entail very significant differences in the basic physical characteristics, consumers' perception or marketing of the various types of PVC Resin (Suspension Grade) falling under the H. S. Customs Headings Nos. 39041000, 39042102 and 39042109. This should, therefore, be considered as one product for the purpose of this proceeding.

2. Like Product

(10) By and large, the PVC Resin (Suspension Grade) exported from Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U. S. A. to India are alike in all respect to the PVC Resin (Suspension Grade) produced and marketed in India.

3. Indian Industry

(11) The contention of the complainant that they represent more than 70 per cent of the total domestic output of the like product and, thus, form a major proportion of the total Indian production in accordance with para 2(c) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985, was verified by the Administrative Department viz., Department of Chemicals and Petrochemicals and found to be correct.

C. NORMAL VALUE

Normal value based on pricing in the exporting country.

(12) As none of the producers/exporters furnished factual information in response to the questionnaire addressed to them, it was deemed to be necessary to determine normal value on the basis of best available information in accordance with rule 14 supra.

D. EXPORT PRICE

(13) The Authority obtained information from the Indian Customs Authorities covering the major imports into India during the investigation period. The information obtained was

considered representative of all transactions of the exporting countries i.e., Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. during this period.

(14) Since none of the exporters responded to the Authority's request to make available the relevant information, the export prices were determined on the basis of the prices actually paid for the products sold, which were found to be reliable. The Republic of Korea representative, however, accepted that their export prices were less than the domestic prices.

E. COMPARISON

(15) For the purpose of a fair comparison between the normal value and export price and in accordance with Section 9(A)(2) of the Customs Tariff Act and Rule 14 supra, the Authority took into account the best available information with it in the absence of any response from the exporters in Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A., who were made a request to make available the relevant information from their end. All comparison on the best available information were made at FOB level.

F. DUMPING MARGIN

(16) Since export varied considerably, normal value for the domestically sold variety of the exports were compared with the export price fob of the comparable variety on the basis of the information available in the absence of any response from the exporters belonging to Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. The margin of dumping varied with different countries. However, the average margin for all imports originating from the said countries into India was substantial.

(17) The Authority has, on the basis of best available information, preliminarily determined the export price, normal value and the margin of dumping in regard to import of PVC Resin (Suspension Grade) from the concerned countries as follows :—

Country	Export Price f.o.b. (\$/MT)	Normal Value (\$ MT)	Margin of dumping % of CIF value
Argentina	442	830	69%
Brazil	447	703	45%
Republic of Korea	512	638	22%
Mexico	461	620	28%
U.S.A.	493	575	14%

G. INJURY

(18) The Authority considered that the effects of imports originating from Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. had to be analysed cumulatively. The exported products of each of the countries concerned were like products, sold or offered for sale in the same market, had common or similar channels of distribution, were simultaneously present in the market and were not negligible as such. Consequently, these imports produced a similar and simultaneous effect on the domestic industry which must be assessed cumulatively.

(19) Under rule 18 supra, for making of determination on the question of material injury or threat thereon, the Designated Authority has to consider "Volume of dumped imports and their effect on prices in the domestic market for like products and the consequent impact of such imports on domestic producers of such products". As regards volume of dumped imports the Designated Authority took into account the fact whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In considering the effect of the dumped imports on price, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the prices of an identical product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

(20) For the examination of the impact on the industry in India, the Designated Authority considered such indices having a bearing on the state of industry as utilisation of capacity; inventories, profits and price trends.

CONSUMPTION IN INDIA

(21) The size of the Indian market had been relatively stable during the period 1988-89 to 1990-91. The total market was estimated at 2,48,000 tonnes in 1988-89, 2,82,000 tonnes in 1989-90 and 2,80,000 tonnes in 1990-91. The availability of PVC Resin (Suspension Grade) was placed during 1991-92 at around 3,39,000 tonnes, an increase of around 21 per cent over 1990-91.

VOLUME AND MARKET SHARE OF DUMPED IMPORT

(22) Imports from countries under investigation increased from 32,307 M. T. in 88-89 to 87,542 M. T. in 90-91 and further to 1,40,909 M. T. in 91-92. It is significant that there was steep increase in imports in 1991-92 despite the severe import compression measures in force. A cash margin on OGL imports of 133% and on special licences of 12590 was imposed on 19-3-91. This was raised to 200% on 22-4-1991 before being brought down to 150% on 8-10-91, 50% on 9-12-91, 25 per cent on 1-1-92 and finally being withdrawn on 12-2-1992. As soon as the import compression measures were relaxed there was a surge in dumped imports. The imports from countries subject to investigation registered an increase from an average of 10,829 M.T. per month during the first eleven months of 1991-92 to 21,794 M.T. in March 1992. The increase in imports was from an average level of 3968 M.T. per month in the first eleven months to 6518 M.T. in the month of March 92 for Brazil, from 925 M.T. to 8626 M.T. for Mexico, from 2596 M.T. to 3582 M.T. from Republic of South Korea and 3134 M.T. to 3322 M.T. for U.S.A.

(23) The market share of imports from the countries covered by the investigation rose from 25 per cent in 1988-89 to 31 per cent in 1990-91 and further to 43 per cent in 1991-92.

PRICES OF THE DUMPED IMPORTS

(24) The Designated Authority investigated whether the exporters from Argentina, Brazil, Republic of Korea and the U.S.A. practised price undercutting during the investigation period. It was seen that while the average price was around \$ 800 per tonne CIF in the first quarter of 1991, it came down to around \$ 700 per tonne on CIF basis in the second quarter of 1991 and was around \$ 560 per tonne on CIF basis in the third and fourth quarter of 1991. In the first quarter of 1992 the average CIF price was around \$ 530 per tonne.

(25) The comparison outlined above shows significant price cutting on the part of the exporters from Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A.

OTHER RELEVANT ECONOMIC FACTORS EFFECT ON INDUSTRY

Installed Capacity and Capacity Utilisation

(26) The installed capacity of Indian PVC Resin (Suspension Grade) industry was 1,41,700, 1,48,440, 1,48,440 and 1,86,973 M.T., respectively, during the years 1988-89, 1989-90, 1990-91 and 1991-92. While R.P.I.L. with a capacity of 1,00,000 M.T. commenced production in December 1991, Chemplast enhanced its capacity from 13,200 M.T. to 28,800 M.T. re-annum, also effective from December 1991. The total installed capacity of PVC Resin (Suspension Grade), on an annualised basis, as on 31st March 1992 was 2,64,040 M.T.

(27) The production of PVC Resin (Suspension Grade) of the Indian industry rose from 1,22,000 tonnes in 1988-89 to 1,63,000 tonnes in 1991-92.

(28) The capacity utilisation of PVC Resin (Suspension Grade) was around 86% during 1988-89 and 1989-90, 89% in 1990-91 and 87% in 1991-92.

INVENTORY

(29) The closing stock position of PVC Resin (Suspension Grade) of the industry may be seen from the following :

31-3-89	5851 M.T.
31-3-90	5247 M.T.
31-3-91	2967 M.T.
31-3-92	16696 M.T. (Excluding IPCL)

There was considerable accumulation of stock at the end of the financial year 1991-92.

VOLUME OF SALES AND MARKET SHARE OF THE INDIAN INDUSTRY

(30) The quantity of indigenous P.V.C. Resin (Suspension Grade) available in India increased by about 34% between 1988-89 and 1991-92, from 1,22,000 tonnes in 1988-89 to 1,63,000 tonnes in 1991-92. Of the total availability, Indian industry accounted for about 49% in 1988-89, around 45% in 1989-90, around 48% in 1990-91 and about 49% in 1991-92.

PROFITABILITY

(31) Of the four applicant companies only three viz. Shriram, D.C.W. and Chemplast have submitted their annual reports showing their balance sheets including the profit and loss account for the latest year, 1991-92. The fourth company R.P.L. has submitted the annual report upto the year 1990-91 when it did not have any production of P.V.C. The three companies were all in profit in 1991-92. The pre-tax profits have increased in the cases of Shriram and D.C.W. while there has been a fall in the case of Chemplast during 1991-92 as compared to 1990-91. However, no conclusion can be drawn from this because they are all multiproduct companies.

PRICE TRENDS

(32) The price trend of the domestic industry showed a steady rise during the years 1988-89, 1989-90 and 1990-91 except for a slight decline in the last six months of the year 1989-90. The increase was maintained during the early part of 1991-92 but a continuous decline is noticeable from January, 1992. The ex-works realisations of Chemplast, DCW, SFC and RPL declined 9.7, 6.1, 9.5 and 11.4 per cent respectively between December 1991 and March 1992. Since price of imports from the countries under investigation showed significant falls during the period January to March 1992, it is clear that the fall in the price of domestically produced PVC resin was induced by the dumped imports. It is also significant that between April 1991 and March 1992 the average monthly CIF value per M.T. declined for four out of five countries under investigation even though substantial exchange rate adjustment occurred during the year from a level of 1 US \$ = Rs. 19.62 in April 1991 to 1 US \$ = Rs. 29.41 in March, 1992.

CONCLUSION ON THE QUESTION OF MATERIAL INJURY

(33) In order to determine whether the Indian Industry is suffering from material injury or threat of material injury within the meaning of rule 18 supra, the Designated Authority took account of the following facts.

1. The market share of imports from Argentina, Brazil, Mexico, South Korea and U.S.A. has increased from 25 per cent in 1988-89 to 43 per cent in 1991-92.
2. There was a surge in imports from these sources during the last quarter of 1991-92, as the import compression measures were phased out in the country.
3. There was substantial price undercutting by all the exporters.
4. Capacity utilisation in the country has shown a steadily rising trend.

174 G/93

5. The inventory increased substantially on 31-3-92 as compared to the position existing on the same date in previous years. A contributory factor to increased inventory was the additional domestic production.

6. Price trends which were steadily moving up registered a decline in the last quarter of 1991-92. The CIF value of imports from four out of five sources of dumped imports declined in Rupee terms in the last quarter of the year despite the substantial downward adjustment of the exchange value of the Rupee.

7. The countries under investigation are all substantial producers of PVC Resin (Suspension Grade).

(34) In determining whether threat of material injury to Indian industry is caused by the dumped imports, the Authority took account of the following facts

(a) Despite the import compression measures taken by the Government of India, there has been an increase in the imports from the sources of dumped imports during 1991-92.

(b) Dumped imports constituted an increasing proportion of total imports during the previous three to four years, the proportion of dumped imports increasing to as much as 84 per cent during 1991-92.

(c) There has been a surge of imports during the last quarter of 1991-92 when the import compression measures were phased out and these imports were mainly from the sources of dumped imports.

(d) Price depression which occurred in the last quarter of 1991-92 coincided with the surge in dumped imports and was clearly brought about by price undercutting by these imports. It is the price depression which has been the main factor behind the determination of threat of material injury.

(35) The capacity utilisation of the Indian PVC Resin industry (Suspension Grade) has steadily increased upto 1990-91 but declined in the year 1991-92. The published financial accounts submitted by the applicants, namely, Shriram, Chemplast, and D.C.W. do not show a decline in the profitability. However, since the financial accounts are for the multi product company, they are not a conclusive proof that the industry has been making substantial profits on sale of PVC Resin (Suspension Grade). In view of the above, it cannot be concluded that material injury to domestic industry has actually occurred. However, it is apparent that if the price trend of the last quarter of 1991-92 and the rapid rise in dumped imports are maintained, decline in profitability and consequent decline in employment, wages, capacity utilisation and financial returns from investment would certainly occur. Inventories are already showing an upward trend. The Designated Authority feels that the overall imbalance in the global demand and supply and the recessionary conditions in the world markets will continue to induce the exporting countries to sell at dumped prices. The Authority, therefore, has come to the conclusion that there is threat of material injury to the domestic industry from dumped imports.

INDIAN INDUSTRY INTEREST**GENERAL CONSIDERATION :**

(36) The purpose of anti-dumping duties is to eliminate dumping which is causing injury or threatening material injury to the Indian industry and to re-establish the situation of open and fair competition on the Indian market which is fundamentally in the general interest of the country.

(37) While Authority recognised that the imposition of anti-dumping duties may affect price levels of the exporters concerned in the Indian market and subsequently may have some influence of the relative competitiveness of their products, it does not expect fair competition on the Indian market to be reduced by the taking of anti-dumping measures particularly if the leave of the anti-dumping duty is limited to the amount necessary to redress the injury. On the contrary, the removal of the unfair advantages gained by the dumping practices is designed to prevent the decline

of the Indian industry and, thus, to help maintain the availability of the widest choice of producers.

(38) The Authority also considered and balanced the effects of anti-dumping duties on PVC Resin (Suspension Grade) imported from Argentina, Brazil, Mexico, Republic of Korea and the U.S.A. in relation to specific interest of the Indian industry and other interested parties including consumers.

INTEREST OF THE INDIAN INDUSTRY

(39) In view of the nature of threat of material injury to the Indian industry, in particular the fact that when a new capacity has come in the Indian industry, it has been forced into the unhealthy situation caused by dumped imports, the Authority considers that in the absence of intervention, the disappearance of certain Indian producers is quite probable. This could entail a severe reduction in the numbers employed and may lead to reduction of the choice suppliers which is not in the interest of consumers.

INTEREST OF OTHER PARTIES

(40) Arguments have been raised that the imposition of anti-dumping measures would be contrary to the Indian public interest because they would result in higher prices less competition and may harm other Indian industries.

(41) Although it is clear that price advantages based on unfair practices are unjustifiable and may in the longer term be harmful even to the interest of consumers when they have the effect on weakening competitors and provoking their disappearances, it is unclear in this case that for the consumers of plastic goods the imposition of protective measures will result in substantial higher prices since PVC Resin is only a raw material which has to be processed before reaching the consumer.

(42) As far as the processing industry is concerned, the extent of any price rise is expected to be limited in view of the fact that a competition between the numerous Indian producers and exporters will not be reduced.

CONCLUSION

(43) In conclusion, after balancing the various interests involved, the Authority considers that the imposition of measures in the present case will re-establish fair competition by eliminating the injurious effects of dumping practices.

(44) The Authority considers that it is, therefore, in the general interest of the Indian public to impose anti-dumping measures in the form of a provisional anti-dumping duty.

(45) For the purpose of establishing the level of the provisional duty, the Authority took account of the dumping margins found and of the amount of duty necessary to eliminate the material injury likely to be sustained by the Indian industry.

(46) Since the threat of material injury has resulted from the price depression caused by the surge in dumped imports during the calendar year 1992, and substantial exchange rate adjustment took place on 29 February, 1992, the weighted average export prices for the product during the investigation period was taken as the basis. These prices were increased by the basic and auxiliary duties of customs to give the price at which the product entered India. For the purposes of determining the cost of production in India, representative Indian cost of production were taken and calculations were made on the basis of data for the investiga-

tion period. After adding reasonable profit margin the domestic prices were compared with the landed price of dumped imports. Both excise duty and countervailing duty were excluded from the calculations. Comparison was made between domestic and imported prices to work out the amount of duty necessary to eliminate the threat of material injury.

FINDING

(47) The Authority accordingly has come to the conclusion that :

- (i) Exporters from Argentina, Brazil, Mexico, the Republic of Korea and the U.S.A. have sold in India PVC Resins, falling under H. S. Nomenclature Code No. 39041000, 39042102 and 39042109, below normal value;
- (ii) The Indian industry is facing a threat of material injury; and
- (iii) There is causal relationship between the dumped imports and threat of material injury.

RECOMMENDATIONS :

(48) Under the provisions of Indian anti-dumping regulations, it would be permissible to levy anti-dumping duties equal to the margin of dumping. However, taking into account the interest of the user industry, the Designated Authority recommends impositions of the provisional anti-dumping duty for a period of four months, from the date of Gazette Notification in this regard, at the rates mentioned against each country :

Country	Rs. per M.T.
Argentina	Rs. 1050/- (Rs. one thousand & fifty only)
Brazil	Rs. 2490/- (Rs. two thousand four hundred & ninety only)
Republic of Korea	Rs. 1700/- (Rs. one thousand and seven hundred only).
U.S.A.	Rs. 1970/- (Rs. one thousand nine hundred & seventy only).

(49) The provisional anti-dumping duty is recommended in terms of rupees per tonne instead of percentage in order to have clarity. This is being suggested taking into consideration all factors. This provisional anti-dumping duty will be collected in cash as all other import duties.

(50) This duty would also be applicable to new or any other exporter from these countries who are not parties to the present proceedings.

(51) The parties/exports concerned may make known their views and apply to be heard orally by the Authority within one month of the date of notification of the provisional dumping duty.

G. SUNDARAM, Designated Authority and Addl. Secy.